Tiria, Kumari Sushila
Tiwari , Shri Narayan Datt
Tripathi, Shri Chandrika Prasad
Tyagi, Shri Shanti
Valiullah, Shri Raoof
Verma , ShriKapil
Verma, Shrimati Veena
Verma , Shri Virendra
Vikal, Shri Ram Chandra
Yadav , Shri Jagdambi Prasad
Yadav , Shri Ramanand
Yadav, Shri Sharad

NOES—1

Gopalsamy, Shri V.

The motion was carried by a rrxtjo-rity of the total membership of the House and by a majority of not less than two-thirds of the Member present and voting.

MR. CHAIRMAN: Now, Shrimati Krishna Sahi, kindly continue your speach.

THE ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION BILL 1987 contd.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : सभापति महोदय, कल मैं सदन में निवेदन कर रही थी कि ...(**व्यवधान**)

[उपसभाध्य (श्री हेच० हनुमनतप्पा) पीठासीन हुए]

उपसभाध्यक्ष महोदय, कल मैं सदन में निवेदन कर रही थी कि ए आई सी टी० ई० द्वारा निर्धारित मानदण्ड, मार्ग निर्देश जो उनके द्वारा किया जाता था, उसके विपरीत कम होने लगा था। परिणाम यह निकला कि बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कालेजों की अनियोजित ढंग से स्थापना हुई और काफी भारी मात्रा में कैपीटेशन फीस एन्ट्री फीस के रूप में ली जाने लगी। अनेक कालेजों में उनकी स्थापना के समय जो इन्फ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था उसकी भी कमी नजर आती थी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कानूनी अड़चन और जो प्रक्रियात्मक कठिनाइयां हैं उनको समाप्त करने के लिये यह विधेयक सदन में लाया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे स्मरण है कल सदन में 5 मुद्दे उभरकर आये थे जिन पर माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये थे। परिषद् के गठन संबंधी, अधिकारों का केन्द्रीयकरण, राज्य सरकारों से विचार, राज्यों के अधिकार और कानकरेंसी, गुणात्मक विकास और संदर्भित उपयोगिता इन 5 मुद्दों पर मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहूंगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के कई सम्मेलन आयोजित किये गये जहां पर ए० आई० सी० टी० ई० को सामविधिक बनाने की मांग का समर्थन हुआ। तत्पश्चात् केन्द्रीय शिक्षु सलाहकार बोर्ड की बैठकों में भी इस विषय पर पूर्ण-रूपेण विचार विमर्श किया गया और इसे स्वीकृत भी किया गया। यह उल्लेखनीय है कि यह संस्था, शिक्षा सलाहकार बोर्ड देश की सर्वोच्च संस्था है, अगर मैं यह कहूं तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। संसद के दोनों सदनों में इसकी मांग की गयी और इसके पूर्व जैसे कि कल कहा गया कि राज्यों से सलाह मश्विरा नहीं किया गया तो सन् 1981 में भी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने ए० आई० सी० टी० ई० को सामविधिक बनाने की मांग की थी। मैं सदन को बताना चाहूंगी कि राज्य सचिवों एवं शिक्षा मंत्रियों से अगस्त, 1985 में विचार विमर्श किया गया, 1986 फरवरी में किया गया, सी०ए०डी० जिसमें सभी शिक्षा मंत्री थे, अगस्त, 1986 में उन लोगों से सम्मेलन में एक विचार विमर्श हुआ, नेशनल डेवेलपमेंट काउंसिल में, शिक्षा मंत्रियों की तो बात अलग है, मुख्य मंत्रियों से भी विचार विमर्श हुआ और उनके जो विचार थे उसी के अनुसार काम किया गया है। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उसमें

मुख्य मंत्री लोग भी रहते हैं। उसके बाद बजट की चर्चा में तथा राष्ट्रीय नयी शिक्षा नीति और प्रोग्राम आफ एक्शन की जब सदन में चर्चा चल रही थी तो उस समय भी सदन में चर्चा हुई, उसके बाद फिर सी०ए०डी० ने जून, 1987 में तकनीकी शिक्षा पर विचार-विमर्श किया।

दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह यह कि राज्य सरकारों के अधिकारों के हनन की चर्चा की गयी। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह शंका बिल्कुल निर्मूल है। इसकी भी चर्चा की गयी और कानकरेंट लिस्ट का सवाल भी उठाया गया था। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि यह शंका निर्मूल है। युनियन लिस्ट की एन्ट्री 66 के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार पर कोआरडिनेशन और मेंटिनेंस आफ स्टैंडर्ड की जो जिम्मेदारी सौंपी गयी है उसी की पृष्ठभूमि में यह विधेयक लाया गया है।

और जो लोक प्राक्कलन समिति की अनुशंसा आश्वासन समिति, राज्य सरकारों के मंत्री, पदाधिकारी, शिक्षाविद, जब इन सबों से विचार-विमर्श कर लिया गया और एक मत से सबों ने इसकी मांग की तथा केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में जब मानिट्रिंग के बिंदु पर विचार हुआ, तो उस समय भी विचार किया गया, फिर यह कैसे माननीय सदस्यों को शंका होती है कि यह प्रजातांत्रिक जो हमारी पद्धति है, उसका हनन् किया गया, या राज्य सरकारों से इसमें विचार-विमर्श नहीं किया गया है;

कुछ माननीय सदस्यों ने कम्पोजीशन आफ दी कौंसिल, परिषद् की संरचना पर अपनी चिंता व्यक्त की है। परिषद् में कुल 51 सदस्यों में से केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधियों की संख्या केवल आठ है। भिन्न-भिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे, राज्य सरकारें और स्वायत्त जो हमारी संस्थायें होंगी, वह स्वयं नाम भेजेंगे और हमारी भारत सरकार के तो बहुत कम लोग इसमें रहेंगे। हरेक राज्य का प्रतिनिधि भी इसमें रहेगा।

कई माननीय सदस्यों ने यह भी बताया कि परिषद् में तकनीकी विशेषज्ञों की संख्या अधिक से अधिक हो। वास्तव में ऐसे ही इसमें प्रावधान भी किया गया है। कुछ पदेन सदस्यों को छोड़ कर शेष सदस्य अपनी विशेषज्ञता के आधार पर ही लिये जायेंगे। परिषद् के सदस्यों में से कुछ जो नामजद सदस्य, विशेषज्ञ ही हैं, जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष होंगे, शिक्षा सलाहकार होंगे या महानिदेशक आई०सी०ए०आर० होंगे, इत्यादि---इन सब लोगों का प्रतिनिधित्व उसमें होगा।

कुछ सदस्यों ने परिषद् की संरचना में अध्यापकों के योगदान की बात चलाई है। तो अध्यापकों का इसमें काफी बाहुल्य रहेगा, उनका योगदान बिलकुल ही कारगर ढंग से लिया जाएगा और सुझाव है कि इसमें विशेषकर आई० आई० टी० के निदेशकों को भी सदस्य बनाया जाना चाहिए। ऐसा सुझाव भी कल आया था। परिषद् में अध्यापकों के प्रतिनिधित्व की व्यास्था भी की गई है, जैसे क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष के रूप में बोर्ड आफ स्टडीज के रूप में प्रोफैशनल जो बाडीज होंगी, उनके रूप में इनमें सभी प्रख्यात शिक्षाविद होंगे। इसमें आई० आई० टी० के निदेशक भी शामिल होंगे।

एक और मुख्य बात उठाई गई थी कि क्षेत्रीय समिति की संरचना जो होगी, उसकी चर्चा भी यहां की गई थी। क्षेत्रीय समिति की संरचना जो अधिकतर राज्यों से होती है, मतलब जो उनके द्वारा मनोनयन किया जाता है, जिसका मुख्य कार्य तकनीकी शिक्षा का विकास करना ही है। अतएव केन्द्रीय स्तर से क्षेत्रीय समिति के लिए जो मनोनयन करने का प्रश्न है, वह बिल्कुल निराधार है।

एक जो माननीय सदस्य ने चर्चा उठाई थी, वह यह कि इस विधेयक के पूर्व ए० आई० सी० टी० के सदस्य जो सचिव थे, वह भी सचिव के स्तर के

[श्रीमति कृष्णा साही]

होते थे, परन्तु अब जितनी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है, उसके संदर्भ में जो सदस्य सचिव हम बनाने जा रहे हैं, वह शिक्षा के सब से उंचे स्तर के जो पदाधिकारी होंगे, उनको इसमें रखा जाएगा ।

किसी माननीय सदस्या ने कल यह प्रश्न उठाया था कि विभिन्न विषयों के पढ़ाये जाने की समुचित व्यवस्था तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में नहीं है । उदाहरण स्वरूप उन्होंने एयरोनाटिकल इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग की बात कही है । यह सही नहीं है । स्वयं तो वह उपस्थित नहीं हैं, लेकिन मैं उनको सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि विधेयक में इन विषयों की विस्तृत सूची तो देना अभी संभव नहीं है, मेरे पास सूची है, यदि वह चाहेंगे, तो उनको भेज दी जाएगी । परन्तु इन विषयों के शिक्षण की भी व्यवस्था है । नई टैक्नालोजी पर विशेष ध्यान देने के लिए तीन निम्नलिखित योजनाएं बनाई जा रही हैं --

1—एरिया आफ मैनेजिंग टैक्नालोजी, जिसमें 16 विषय लिये जायेंगे ।

2– एरिया आफ टैक्नालोजी—जहां कमी आती है, जिसमें दस विषय लिये जायेंगे, और

3– इम्प्रूव्ड एण्ड स्पेशलाईज्ड फील्ड्स आफ टैक्नालोजी, इसमें 46 विषय लिये जायेंगे ।

इसकी सूची भी मेरे पास है, जो मैं भेज सकती हूं ।

इसके अतिरिक्त इन लोगों ने यह भी सवाल उठाया था कि देहाती क्षेत्र को इसमें इग्नोर किया गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है । रूरल टैक्नालोजी का इसमें ध्यान दिया गया है ।

अब मैं संक्षेप में कहना चाहती हूं कि यह जो विधेयक है, उसमें प्रावधान है कि नई तकनीकी संस्थाएं एवं उनमें नये पाठ्यक्रम ए० आई० सी० टी० की अनुमति प्राप्त कर ही प्रारम्भ किये जायेंगे । तकनीकी संस्थाओं के द्वारा लिए जाने वाले शुल्क का मापदण्ड ए० आय० सी० टी० ही निर्धारित करेगी । मेरिट पर नामांकन से प्रवेश के लिए ए० आई० सी० टी० नियम बनाएगी । तथा तकनीकी संस्थाओं का मार्गदर्शन करेगी । यह सारा प्रावधान किया गया है । यह तकनीकी संस्थाओं के पाठ्यक्रमों का समय-समय पर मूल्यांकन करेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर ऐसी संस्थाओं को भी डिरोक-नाइज करेगी जो ए० आई० सी० टी० के क्रायटेरिया को फुलफिल नहीं करेगी । तकनीकी शिक्षा में गुणात्मक विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्य किए जाएंगे और यह व्यवस्था की जाएगी कि महिलाएं, विकलांग तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश मिल सके । यह तो इसके प्रावधान हुए । इसके साथ ए० आई० सी० टी० को जो संविधिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे । तो उसमें तीन मुख्य बातें आएंगी—संपूर्ण देश में तकनीकी शिक्षा पद्धति का आयोजन और समन्वित विकास, तकनीकी शिक्षण का योजनाबद्ध तरीके से विकास तथा उसके गुणात्मक विकास में वृद्धि । तकनीकी शिक्षा पद्धति का नियमन, मापदण्डों तथा स्तरों को व्यवस्थित किया जाएगा ।

सभापति महोदय, अगर ऊपर के दो नम्बर में जो बातें बतायी हैं ये अगर अच्छी तरह से रेगुलेट हो जाएं तो फिर रेगुलेशन के रूप में इसे अधिक काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी । बल्कि यह जो विधेयक है इसकी भूमिका केवल रेगुलेशन के रूप में नहीं है बल्कि इसमें कोआर्डिनेशन, प्लानिंग और क्वालिटी सभी इसमें शामिल हैं । मैं आशा करती हूं कि माननीय सदस्यों ने जो बिंदु उठाए हैं, जो समस्याएं उठायी हैं, उनका मैंने निराकरण किया है और अंत में यही कहूंगी कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसकी कार्य-योजना को अनुमोदित करते समय अन्य बातों के अलावा शिक्षा परिषद् को संविधिक अधिकार प्रदान करने

के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत करने की व्यवस्था थी ताकि वह परिषद् को सौंपी गयी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सके। मैं सदन से निवेदन करूंगी कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने एवं तकनीकी शिक्षा के विकास की गति को तेज करने वाले इस विधेयक को पारित किया जाय। यह मेरा निवेदन हैं।

THE VICE-CHAIRMAN: (SHRI H. HANUiMANTHAPPA): The question is :

That the Bill to provide for the establishment of an All India Council for Technical Education with a view to the proper planning and coordinated development of the technical education system throughout the country, the promotion of qualitative improvement of such education in relation to planned quantitative growth and the regulation and proper maintenance of norms and standards in the technical education system and for matters connected therewith, be taken into consideration .

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 *to* 25 were *added to the Bill.*

Clause 1, the enacting formula and the Title were added to the Bill .....

श्रीमती कृष्णा साही : मैं प्रस्ताव करती हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

The question was put and the motion was adopted.

On Price Situation in the Country— Short Duration Discussion —contd.

श्री शरद यादव (उत्तर प्रदेश) : उपाध्यक्ष महोदय, मंहगाई के ऊपर चर्चा हो रही है। इस चर्चा के महत्व का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज पूरी सरकार गायब है। अगर कृष्णा साही जी बैठी न होतीं तो इनका विधेयक नहीं आता।

श्रीमती कृष्णा साही : जी ?

श्री शरद यादव : यदि आपका विधेयक नहीं होता तो शायद आप भी यहां नहीं होतीं। उपसभाध्यक्ष जी, मैंने कल भी कहा था कि इसका वक्त जो आपने रखा है, इसने विषय के महत्व को घटाया है। परसों, बीता हुआ परसों, जब मैं श्री एच० के० एल० भगत जो मंत्री हैं भारत सरकार के, उन की सफाई सुन रहा था। इस बहस के बीच में ही उन्होंने अपनी सफाई देने का काम किया। उन के वक्तव्य को मैं ने बहुत ध्यान से सुना और लगातार जो तीन, चार दिन से मंहगाई पर बहस हो रही है उसको मैं ने ध्यान से सुना है। जब भगत जी बोल रहे थे तो मैं ने देखा कि उन का पूरा बयान सतही था। वह मंहगाई का मुकाबला कैसे करेंगे इस के लिये उन का पूरा बयान सतही इलाजों से भरा हुआ था। वह जोर जोर से मंहगाई को डांटने डपटने का काम जारी किये हुए थे और मुख्य रूप से महंगाई के मुकाबले के लिये उन्होंने दो उपाय बताये। नम्बर एक यह कि पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को वह दुरुस्त करेंगे और नम्बर दो कि कंज्यूमर मूवमेंट को मजबूत करना है। आप उन के पूरे बयान को मनोयोग से देखने का काम करिये, उन्होंने इन दो के अलावा कोई तीसरा उपाय नहीं बताया। मैं अपनी बहस को शुरू करने से पहले कहना चाहता हूं कि इस सवाल को राजनीतिक सवाल नहीं बनाया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर इस सवाल को राजनीतिक सवाल न बनाया जाये, लेकिन जो कारण महंगाई बढ़ने के हैं उन पर

[श्री शरद यादव]

यदि पूरी बहस नहीं होगी तो उन कारणों का निदान नहीं होगा और उसका मुकाबला नहीं किया जा सकेगा। महंगाई सरकार के सामने और इस देश के गरीब लोगों के सामने एक चुनौती है। इस के कारण क्या रहे ? उसका मुकाबला कैसे होगा ? इस पर बहस नहीं होगी तो मैं मानता हूं कि महंगाई को रोकना आपके वश में नहीं होगा। देश की आजादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना में महंगाई स्थिर रही है। 15 प्रतिशत उस समय महंगाई की मान्यता थी और उसके बाद जितनी पंचवर्षीय योजनायें आती रही हैं लगातार उनमें यह बढ़ती रही है। दूसरी योजना में 25 फीसदी, तीसरी में 35 फीसदी, चौथी योजना में 45 फीसदी और पांचवीं योजना में तो 60 फीसदी महंगाई बढ़ गयी और छठी में फिर 45 फीसदी बढ़ी और सातवीं योजना के दौर से तो हम गुजर रहे हैं और फिर भी इस रोग की चर्चा और उस पर बहस में हम तीन, चार दिन से लगे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि लगातार देश में आजादी आने के बाद महंगाई बढ़ती रही है और महंगाई बढ़ रही है। जो कांग्रेस पार्टी, सरकारी पार्टी के संसद् सदस्य हैं उनकी जबान से, उनके मुख से भी सुनने को मिला कि 1947 के एक रुपये की कीमत आज एक पैसे से भी कम है। वीरेन्द्र पाटिल जी उनके मंत्रिमंडल में रहे हैं। उनका कहना है कि आज एक रुपये की कीमत 1960 के मान से 12 पैसे है। सरकार कहती है कि 13 पैसे है। मेरे कहने का मतलब है कि कभी इतिहास में हमने सुना था कि जब चीन में दूसरे विश्व युद्ध में महंगाई बढ़ी थी तो चीन का आदमी झोले में नोट भर कर ले जाता था और जो सामान खरीद कर वह लाता था वह उन नोटों से कम होता था। चीन में यह परिस्थिति थी कि जितने नोट वह ले जाता था उससे कई गुना कम वजन का सामान वह बाजार से ला पाता था। हिन्दुस्तान में भी यही हाल होने वाला है। जो महंगाई के कारण हैं उन पर बहस हो ले का काम नहीं हुआ। विरोधी पक्ष के लोगों ने अपनी बात रखी है और आंकड़े देने का समय नहीं है। यह बहस बहुत लम्बी चली है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे विरोधी पक्ष के लोगों ने इस संपूर्ण रोग की तरफ आप का ध्यान लाने का काम किया है। महोदय, उत्पादन साधनों से लेकर जो आपका घाटे का बजट है जो फिजूलखर्ची है, जो आपने हिन्दुस्तान में आजादी के बाद चलाई है, आजादी के आंदोलन का जो बहुत बड़ा सिद्धान्त था मितव्ययिता को, उसको आपने छोड़ा है, उससे हिन्दुस्तान की बरबादी हुई है। हमारे माननीय तिवारी जी कभी जवानी की उम्र में अच्छाइयों से भरे हुए थे। मैं उस जमाने के तिवारी जी को कहना चाहता हूं कि उनका उस समय का जो दर्द था वह आज तक बना हुआ है, भले ही वह सरकारी पार्टी में चले गए हैं। लेकिन हिन्दुस्तान के गरीबों के कष्ट बढ़े हैं, हिन्दुस्तान की गरीबी बढ़ी है। हमने सब तरह के खर्चों का जिक्र छोड़ दिया, लेकिन सुरक्षा और पुलिस का ही खर्च आजादी के बाद से लगातार बढ़ता गया है। आजादी के बाद से आज तक पुलिस का खर्च 27 फीसदी बढ़ गया है। बजट आपका लगातार बढ़ता जा रहा है सुरक्षा और पुलिस के मामले में आपकी जान खुद फंस गई है, आपको अपनी जान बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। देश की सुरक्षा का जहां तक सवाल है, उसको तो मैं मान लेता हूं, लेकिन देश की सुरक्षा में भी हमने बहुत ही ज्यादा खर्च करना आरम्भ कर दिया है। हमने फौज पर इतना खर्चा बढ़ा दिया है, जब कि हमारे देश का कोई दुश्मन नहीं है। पहले हिन्दुस्तान एक था उसके दो टुकड़े हो गए, उसके अलावा हमारी किसी से लड़ाई नहीं है। अरबों रुपया हमारी सुरक्षा के नाम पर चला जाता है। हमारी किसी से लड़ाई नही है, किसी से मुकाबला नहीं है। चीन के साथ हम मुकाबला करना ही नहीं चाहते। माननीय तिवारी जी विदेश मंत्री भी थे, वित्त मंत्री अब हैं और सदन के नेता हैं। लेकिन तिब्बत जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है

उस पर हम चीन से बात नहीं करते। पाकिस्तान कुछ करे तो फौरन हम उसके बारे में बोल देते हैं। इसलिए आपकी नियत साफ नहीं है। हम केवल कमजोर को दुश्मन देखना चाहते हैं। पाकिस्तान की आबादी हिन्दुस्तान से कई गुना कम है। 9 पर हम 80 मैंबर हैं। 9 के साथ हम 80 लोगों को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन हमारा अरबों रुपया सुरक्षा पर खर्च होता है। हमने भवन निर्माण के लिए एशियाड किया। उससे लेकर आज तक फिजूल खर्ची कम नहीं होती है। हमने कई तरह की कटौती न करने का काम किया है, नए टैक्स लगाने का काम किया है। अगर हम फिजूलखर्ची रोकते तो टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। घाटे की अर्थ-व्यवस्था हमारी बीमारी है, हिन्दुस्तान का जो उत्पादक है, जो अपना पसीना बहाकर उत्पादन करता है उसको वाजिब दाम नहीं मिलता। हिन्दुस्तान के खेत, खलिहानों में और कारखानों में उत्पादित माल के दामों में कोई समन्वय नहीं है। लगातार आपने अय्याशी का जो सामान बनाने वाले कारखाने हैं उनको बढ़ावा दिया है, आपने फिजूलखर्ची और उपभोक्ता संस्कृति को पनपाया है जो हिन्दुस्तान में महंगाई बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण रही है। आपने टी वी से लेकर जो संचार की व्यवस्था है, जिस पर आपने पैसा खर्च किया है जैसे कंप्यूटराइजेशन पर, माडर्नाइजेशन पर, इन सारी बातों से हिन्दुस्तान का बेरोजगार और बेरोजगार हो गया है। लाखों करोड़ों हाथों को आप राष्ट्र निर्माण में लगाते, लेकिन वे आज बोझा बने हुए हैं, वे बेकार पड़े हुए हैं। उनसे हम राष्ट्र निर्माण का काम नहीं लेते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि हमने जो मेहनत करने वाले हैं उनको वाजिब दाम नहीं दिए, उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा दिया, अय्याशी के जो कारखाने हैं वे आपके मुनाफा कमा रहे हैं और बाकी उत्पादन के कारखाने घाटे में चल रहे हैं। जो उद्योग धंधे हमारे हाथ में हैं, जिनमें सरकार मिनरल्स पैदा करती है वे कारखाने सरकार के हाथ में हैं लेकिन लोहे बनाने के कारखाने घाटे में चल रहे हैं। यानी सारे कारखाने घाटे में चल रहे हैं। खाद के कारखाने घाटे में चल रहे हैं इसलिए कि दाम नहीं बढ़ रहे हैं। खाद के दाम जिस तरह से बढ़ने चाहिये थे नहीं बढ़ रहे हैं। खाद के कारखाने व्यवस्थित तौर पर नहीं चलाए जाते। उनकी जितनी कैपेसिटी है पैदा करने की उतनी वह पैदा नहीं करते। अगर किसी खाद के कारखाने की कैपेसिटी 100 फीसदी है तो वह कारखाना 25, 30, 35 फीसदी खाद ही पैदा कर रहा है। इसके कारण ही खाद की कीमतों में कमी आयी है। जो कारखाने सरकार के हाथ में है जैसे लोहे के, ताम्बे के, रेल के, डाक के उनकी कीमतों का क्या हाल है आप जानते हैं। जो पूंजीपति हैं वह व्यापार करके मुनाफा कमाना चाहते हैं उससे ज्यादा हमने मुनाफा कमाना शुरू कर दिया है। हमारा प्रबन्ध निकम्मा है। पब्लिक सेक्टर के जो प्रबंधक हैं, प्रबन्ध करने वाले हैं वे सरकारी अफसर हैं। वे सब निकम्मे हैं, ठीक प्रबन्ध नहीं करते। पब्लिक सेक्टर बराबर बदनाम हो रहा है। यह एक सफेद हाथी हो गया है। पूरे देश की सम्पत्ति को खाता रहता है जिससे महंगाई बढ़ती जाती है। मेरा निवेदन यह है कि महंगाई बढ़ने का कारण काला धन है। मैं आपको बताना चाहता हूं 5 हजार करोड़ रुपये की पैरलल इकोनोमी हमारे देश में है। भ्रष्टाचार का यह हाल है कि हमारी सम्पत्ति जो विकास पर खर्च होनी चाहिए वह सम्पत्ति किसी न किसी प्रांत के दो-तीन निजी जेबों में जा रही है। वह निजी जेब सरकार से मिले हुए हैं, सरकारी पार्टी से मिले हुए हैं। महंगाई का मुकाबला करना चाहते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि सेन्ट्रल हाल में बुलाइये कांग्रेस पार्टी के लोगों को। उनसे कहिये कि इस सूखे के मौके पर, संकट के मौके पर आप शपथ लीजिए, अगर आप हमें भी बुलाना चाहते हैं तो हम को भी बुला लीजिए। हम आपके साथ हैं। हमारे हाथ में खाने-पीने का काम नहीं है। हम शपथ लेते हैं कि अगर आप अपने सदस्यों को, मैम्बरों को शपथ

5.00 P.M.

[श्री शरद यादव]

दिला दें तो मैं सोचता हूं कारगर कदम होगा ।

आप कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक करेंगे । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह आपके बसका नहीं है । जमाखोरों को आप पकड़ेंगे नहीं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई आप करेंगे नहीं । कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोगों को, इस पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ताओं को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगाया हुआ है । क्या आप उनको ईमानदारी के रास्ते पर ले जायेंगे ? (समय की घंटी) में चार दिन से बैठा हूं । मुझे थोड़ा टाइम और दे दीजिए । मैं अपनी दो-चार बात कह कर समाप्त करता हूं । तिवारी जी यहां बैठे हुए हैं । उनको दो-तीन सुझाव देकर समाप्त कर दूंगा ।

आप अपने सदस्यों को सच्चा, ईमानदार बनाने का प्रयास कीजिए । यदि आपको लगता है हम आपके साथ आयें तो हम आपके साथ कसम खाने को तैयार हैं । हम ईमानदारी और सच्चाई के साथ मुकाबला करेंगे । बंगाल में फैमिन पड़ा था । उस फैमिन में अनाज बहुत था, इतिहास पुराना उठाकर देखेंगे तो पता चल जायेगा लेकिन लोग भूख से मर गये । इस देश में अनाज का भंडार है । कल भगत जी भी कह रहे थे कि बाहर से भी अनाज मंगाने वाले हैं । 1.5 मिलियन टन अनाज आप आयात करने वाले हैं । रूस के साथ आपने अनुबंध किया भी है । आप बाहर से अनाज मंगाना चाहते हैं । इसी के साथ आडिबल आयल की समस्या भी हल नहीं हो रही है । मैं कहना चाहता हूं कि आपके सारे उपाय हंगाई बढ़ाने वाले हैं । बंगाल में फैमन पड़ा था तो लोग छटांक-छटांक अनाज तक की मांग कर रहे थे । आप पता लगा लीजिए उस जमाने में क्या हालत थी । बंगाल के फैमिन में जो लोगों को मजदूरी मिलती थी वह बहुत कम मिलती थी । वह उससे आज भी नहीं खरीद सकते हैं । अनाज भी देख लीजिए कि छः महीने पहले जो मजदूरी मिलती थी और आज जो मिलती है उसमें बहुत फर्क है । वह अब भी उस मजदूरी से अनाज नहीं खरीद सकता । एक-दो किलो अनाज भी नहीं खरीद सकता यह हालत हो गयी है हमारे देश की । हमारा देश कंगाल और लाचार है । इसकी कहावतें भी लाचार और कंगाल हैं । इन कहावतों को भी लकवा मार गया है । वे सूख गयी हैं । इस देश में कहावत थी कि किसी से पूछिये कि कैसे हैं भई, तो वह कहता था नमक रोटी खा रहा हूं बढ़िया । दाल रोटी चल रही है मजे में । यह अब कहा जाता है मैं कहना चाहता हूं कि कहावतों को भी लकवा मार गया है । लाचार हो गयी हैं कहावतें, बेबस हो गयी हैं कहावतें । आज नमक भी दो रुपये किलो मिलता है । आजादी के पहले के और आजादी के बाद के दामों को लीजिए । पता लगेगा कितने दाम बढ़ गये । अब लोग कहते हैं रोटी चटनी खा रहे हैं । चटनी जिससे बनती है उस प्याज की कीमत भी पांच रुपये किलो है और छः रुपये किलो हरी मिर्च है । मिर्च महंगी हो गयी तो चटनी नहीं बनेगी । यहां रोटी और चटनी भी महंगी है । दाल 11 रुपये किलो हो गयी थाली रोटी और दाल भी नहीं खा सकते । दाल 11 रुपये किलो हो गयी ।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : आप समाप्त करियें ।

श्री शरद यादव : चटनी महंगी है, नमक महंगा है, दाल महंगी है, चटनी रोटी महंगी है, नमक रोटी महंगी है और दाल रोटी महंगी है । महंगाई यहां तक पहुंच गई है । माननीय तिवारी जी आप कहते हैं कि इस बार भूख से कोई नहीं मरेगा । अन्न का बहुत बड़ा भंडार है आपके पास । लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस अन्न के भंडार को जो आपके पास है, उसको कैसे बांट पाओगे क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर है । क्या आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना सशक्त है जो वह बांट पायेगा ? मैं ऐसा नहीं मानता हूं । महोदय, जिस तरह से इन चीजों को पुराने रवैये और ढर्रे पर आपने चलाया है इसके चलते

ऐसा मानने के लिय मैं तैयार नहीं हूं। कल यदि मान लिया जाय कि पिछले साल की तरह कोई संकट खड़ा हो जाय, ईश्वर न करे कि ऐसा हो तो आपके इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सहारे मैं यह मानता हूं कि आप भी डूबोगे और देश भी डूबेगा ऐसी महंगाई बढ़ने वाली है। (समय की घंटी)

महोदय, आप बार-बार घंटा बजा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : आपकी पार्टी का एक मिनट का समय था, 16 मिनट हो गय।

श्री शरद यादव : इन शब्दों के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन कारणों से महंगाई बढ़ी है उनका आप पुख्तावला करियें। जब तक आप इसको रोकने के लिय कारगर कदम नहीं उठायेंगे आप इसमें सफल नहीं हो सकते। आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ठीक नहीं है, कंज्यूमर मूवमेंट तत्काल ठीक नहीं हो सकता है इसलिये आप दूसरे उपायों की तरफ निगाह डालिये, तभी आप इसके लियें कोई रास्ता निकाल सकते हैं। इन शब्दों के साथ आपने जो मुझे ज्यादा समय दिया उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं।

V SHRI SANTOSH KUMAR SAHU (Orissa). Mr. Vice-Chairman, Sir, at 'he outset, I thank Mr. N.E. Balaram and others who have brought this very critical issue for discussion before the House. Sir, there is no doubt that this country is passing through a very critical phase of price rise since July, 1987 coupled with natural calamities like the worst drought and tha severe floods in some of the States. But, Sir, what I say is that I have been hearing from the beginning and I do not agree with the prophets of doom or disaster. I say we require now all the courage to meet the crisis. Only the same note of disaster or doom may sometimes discourage the groundworkers who are trying to fight that out. So. my humble suggestion would be now let us see what sort of natural calamities we are facing, what the problems are today what the problems is of price rise. Let us have a critical analysis.

Sir, we have seen tha reports and one of the most eminent economists, Mr. Swaminathan has said that in the rice-growing areas of Asia drought and flood ravages have caused a great damage and India i_s likely to suffer a damage of 20 million tonnes of rice. And the FAO has also said that a 5 per cent increase or decrease in the production of the developing countries of the world creates a great problem for the economy to manage. And the price rise Sir, is so high that the marginal people and the poor people suffer very much. Thanks to our sound economic management, we had a buffer stock of 23 million tonnes of cereals as a result of which up till now we have not become so critical as it was in other countries today. But at the same time I would like to say that we have to take a cautious note for the future. Suppose we have depleted 23 million tonnes Reserve Of foodgrains and the crop also failed in future, how can we build up the confidence, how can we feed the teeming millions of people in the country in future? And absolutely the impact of price rise this year i_s very much on the poor people and they have no purchasing power because of the ravages of drought and floods. So I would say that at the same time we have to gear up all the rural development programmes. NREP, etc. The people who depend upon agriculture, who are 70 per cent of the population, have no purchasing power to get the daily essential supplies.

Now coming to the other point. Sir. if we analyse the price stituation in our country, there is a continuous rise of prices from year to year from the beginning of planning. That is one aspect. And there is a periodical rise in a particular period of time, from July t.-, November, every year. Now we have romc- to this critical situation. Sir. it is true that in a developing economy there is a certain

[Shri Santosh Kumar Sahu]

expected rise in prices to some extent. But if necessary steps are not taken to check them there will be a great deal of misery to the common man because this price rise will affect the common man more than the other categories.

Then, Sir, I would like to tell you and through you to the Government that the Reserve Bank had earlier in its Annual Report of 1986-87 cautioned the Government that during 1987-88 there will be a tali in production of both agricultural goods and industrial goods and also that there will be certain inflationary trends, which the Government should manage skilfully so that not much damage is done to the Government's economic policy. These things are on record.

Then_ Sir. it is rece-sssry that we sec the other side also. It is true that the rice-growing areas have suffered. These rice growing areas have been affected either by floods or by drought. But floods and drought are not a new phenomena in this country: These affect our country in a cyclic order. What wo require is dynamic planning if we want to overcome these cyclic disasters. In every decade two or three such droughts and floods hit our country and these very badly affect our economy. What is necessary is that we must have a periodic planning to meet these eventualities. That is the sign of a sound economic policy. One of the ways by which this can be done is by laying stress bn more' high-yielding varieties of paddy, alternative crop pattern production and dryland farming and also water management. These things should have been thought of much earlier "o that these droughts and floods could not have created such a havoc in the economic life of our country.

Sir, coming to the question of . pulses, we have seen that this year the production will be less than that of last year. It will fall short By five to six lakh tonne?. Now. you can see. for example, the case *of.* edible oils.

We have seen the Supply Minister saying that they are trying to import something from outside. But this is not reaching the rural poor. Through the PDS wa are trying to improve the supply position. The common man is hard hit. The price of mustard oil has gone up by more than 40 per cent. Similarly the prices of groundnut oil and other edible oils have risen very high. The question is why these essential items, like edible oils, which are poor man's food they have to take a little quantity of these things, why not have a better public distribution system for them? Why has the public distribution system failed today? The question is whenever we think of improving the public distribution system, only then a crisis comes. We though during Chinese War in 1962 that the Consumer moment the PDS moment, will be improved. We very much wanted to improve them. Then drought and calamities came and....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Please conclude now.

SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: I have just begun only. Please give me some more time.

Sir, I say that if inflation is not contained the benefit of planning, the benefits of enonomic policy will not be visible, and prices will eat away everything and it will make poor man's like dry they wi'lj suffer immensely. So Sir. I would like to emphasise on you and through you lhat the price policy, the overall price policy, is related to the level of the economic policy of the country the fiscal policy, monetary policy and other welfare measures of the Government. If we want that the pricing policy has to play a very effective role in the instrument of the economic poliev of the Government we have to see that this is clone effectively.

Sir. I was seeing into the various reports. In 1964, there was the Jha Committee Report for fixing the

pnce of wheal and fice. Now, the FCI was created in 1976, Then we set up the Bureau of Costs and Industrial Prices. Then the MRTP was set up-But all of them look into singular aspects only. There is not an integrated scheme to control price policy. We should have a coordinated effort. It is necessary as they have in other countries like France where they have a National Price Policy Commission. So also they have in the U.K. Like that it is necessary that there must be a price commission in our country also which will look into the cost effectiveness of production and also the selling price and also to see to its implementation There have to be permanent measures. Ad hoc mea-• sures will not improve our economic position and we cannot meet the challenges posed by the price rise, the drought and the floods.

As many hon. Members pointed out, the Reserve Bank of India has also said that there may be industrial recession, and the Reserve Bank has forecast that the GNP will come down to 1.7 percent. So. in the coming years it would be a critical stage. We have to build up our economy; we have to build up food reserves and we have to see that the purchas-ing power of the poor man improves so that he is able to buy essential commodities. For that, we have to streamline our administration. We have to make our public distribution system a thorough system so that the poor people can survive.

Then, Sir, rural employment programmes has to be geared up and we have to work towards industrial growth and stability which is very essential for our economic growth, without which we may not succeed. These are very important issues faced by us due to price rise and I Trope it will be effectively tackled both by the Central Government and the State Governments. It requires a national perspective where all the parties must also cooperate. This is a problem which can be tackled keeping in mind our national goal and if we have the cooperation of eveiy-body_ we can solve this problem as we nave crossed many periods of struggle, and I am sure we will he able to solve this problem as well. Thank you.

SHRI UHULAM EASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): I rise to speak en the subject of price rise. In the first instance, I may have to make an observation thai our country is a continent, in itself. The latest figures given by the Reserve Bank of India indicate that the average inflation rate in the developing countries is to the order of 42 per cent, whereas we have been able to contain it within 10 to 2 per cent. Thi$_s$ is not a small achievement by itself. We have also to keep in mind the fact that we have not had a single case of starvation death so far in the country. This needs to be kept in view while we are discussing the situation of price rise.

But. Mr. Vice-Chairman there are some grey clouds on our horizon. The majority of our populace consists of lower middle classes and lower class people. We have to concentrate on the price situation in respect of 10 or 11 essential commodities. 'These include cereals, edible oils, pulses, vege-tables_ cloth and one or two other things. The point at issue is that with regard to edible oil for instance, the hon. Minister of Civil Supplies is not here, only the day before yesterday, I was just in the lobby and Mr. Ram Chandra Vikal was there. I asked him whether he takes rice. He said, no_ I never take rice. We people from UP take only wheat. You may take the case of people from Kash-mir. We take rice both times. Such factors ought to be taken into consideration. I have to bring to the notice of the Government a very startling situation. This morning at 9 O'clock, I heard the news from the All India Radio and the news gave me great alarm. It said that in Haryana, 11.7 lakh tonnes of rice had come to man-dis and out of that, ouly 1.1 lakh tonnes have been procured by the

[Shri Ghulam Rasool Matto] Government. You can understand that—as the Minister has also*G* said— while the situation with regard to wheat is comfortable., .the situation in regard to rice is not comfortable. We may have to resort to imports also. The reason is obvious, *(lime belt) ings)* Sir, I have just started.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA: Please try to conclude.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: I am only making pointed references. Interruptions take away m_y time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMAN THAPPA): There are no interruptions.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Sir, the point is. when a farmer in Haryana gets Rs. 2.35 per kg. of paddy from Private Traders, why should be -sell it at Rs. 1.69 or so? This is a subject which you have to attend to.

By God's we have a buffer stock. If we had not the buffer stock, what would have been the position? God forbid_ if we do not have good monsoon next year also. In that case, our buffer stock will get further deplated. We should take every care to see that the bulfer stock is maintained. It should be maintained at a reasonble level.

I have with me a statement which says that the Planinng Commission hag two objectives before it. The first is to contain inflation The second is in regard to the balance of payments position. These are the two objectives. These are the two directives given by the Finance Minister as well. The Prime Minister is on record having said that the deficit of Rs. 5850 crores will not be exceeded. There has been an unprecedented drought. We have tried to raise some resources by way of additional taxes etc. I would request the hon. Minister to see to it that the deficit does not exceed this limit, except, of course when there are un.

avoidable situations. If we exceed this num. naturally, the inflation rate will shoot up and we cannot stop it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): *Please* conclude.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: The non. Minister is in charge of both me finance Ministry and the Commerce Ministry. The second objective which t mentioned is relevant here, the trade deficit is of the order of 9,000 crores. this is a matter of concern. 1 think, ihe new import-export policy is on the anvil. 1 believe the present policy is valid up to 31st March, 1988. Never mind if it ends later. You can scrap it even now. In view of the tight foreign exchange situation, 1 would request the hon. Minister that there should be no such thing as Open General Licence. This should be scrapped. Here, we have to understand one point. As against exports, we are allowing people to import raw materials. If a particular person who has obtained an Import Licence is a Manufacturer or an exporter only, he can sell that licence in the market. Those persons who are in need of more raw materials can buy the Replenishment Licence and make good their requirements. But to have an Open General Licence and to spend free foreign ' exchange on import of raw materials is not possible. You have to restrict it. You have to do something about it. You cannot allow unrestricted or unregulated import of these items.

Now, Sir, about edible oil. Earlier, I wanted to mention it but I was speaking in the context of wheat and rice. The point that I want to make is, in West , Bengal and other eastern parts, they want - only mustard oil. They do not want any f other oil. Mustard oil is a very important ingredient of essential commodities for them. There may be other more nutritious oils but these people prefer only mustard oil. Now, if the Government allocates mustard oil to vanaspati manufacturers, the whole balance would be up-

set. Therefore, I request tha; allocation of mustard oil to vanaspati manufacturers should be immediately stopped. When they are getting palm and other oils, why should they get mustard oil also?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): Mr. Malaviya. Mr. Matto, I am sorry. We have to conclude the discussion today and there are a few more speakers.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Sir, I hope 'he hon. Minister will take into consideration the points I have made.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपाध्यक्ष जी, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, लगता है वह लाईलाज है क्योंकि न केवल इस वर्ष बल्कि पिछले तीन वर्षों से लगातार जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं, आम आदमी के खाने-पीने की चीजें हैं, दाल है, सब्जी है, दूध है या दूध से बने अन्य पदार्थ हैं, खाने का तेल है, चीनी है, नहाने का साबुन है, कपड़ा धोने का साबुन है, सब की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है । इसके पीछे हमारी समझ में जो बात आती है, वह यह है कि जो आज बहुत से कानून हैं, जिसकी चर्चा कल माननीय भगतजी ने की--जैसे इसेन्सियल कमोडिटीज एक्ट, 1955 है, उसके बाद चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1986 या जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है या सहकारी समितियों के जरिए जो बहुत सी चीजें आम आदमी को बेचने की व्यवस्था है, उनका संचालन, मान्यवर, ठीक नहीं हो रहा है । आज केवल महंगाई ही नहीं बढ़ रही है बल्कि बहुत सी ऐसी भी चीजें हैं जो आम आदमी को मिल नहीं रही हैं । इसका एक कारण और भी है कि जो रुपए की क्रय-शक्ति है, उसका, बराबर अवमूल्यन हो रहा है । जुलाई 1985 में रुपए की कीमत 16.55 पैसे हो गयी थी, जुलाई 1987 में घटकर 15.20 पैसे रह गयी और अगस्त, 1987 में यह घटकर 13.6 पैसे हो गयी है । इस प्रकार जो रुपए का अवमूल्यन हो रहा है और जो रुपए की क्रय-शक्ति बराबर घट रही है, उसको रोकने में सरकार असमर्थ रही है ।

मान्यवर, थोड़ी बहुत महंगाई होती है तो उससे सबसे ज्यादा तकलीफ जो नौकरीपेशा लोग हैं, जिनकी छोटी आमदनी है, उनको होती है, उनको इसका कष्ट भोगना पड़ता है । आप महंगाई बढ़ा देते हैं, इससे जो उनकी क्रय-शक्ति है वह बढ़ नहीं जाती है क्योंकि जितनी बाजार में आवश्यक चीजें हैं, उनमें कीमतों में वृद्धि होती है और जब महंगाई और बढ़ा देते हैं तो ले-देकर सब बराबर हो जाता है । मेरी राय इस बारे में यह है कि एक राष्ट्रीय दाम नीति तय हो जानी चाहिए । जब तक यह तय नहीं होगी और जिन कानूनों की कल भगत जी ने चर्चा की, उनका कड़ाई से पालन नहीं किया जाएगा, इसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला है ।

मान्यवर, यह एक स्टडी रिपोर्ट है । इसमें चर्चा की है कि जिस तरीके से चीजों की कीमतें बढ़ी हैं, यह अप्रैल, से लेकर सितम्बर तक की रिपोर्ट है—

During the period April to September 1987, there was a sharp rise of 32.0 per cent in the commodity group of edible oils.

केवल खाने के तेल में इस स्टेडी रिपोर्ट के हिसाब से 32 परसेंट की वृद्धि हुई है, लेकिन जो बाजार की हालत है, उसके हिसाब से 40 परसेंट की वृद्धि हुई है ।

Other groups which showed similar increase include oilseeds 30.6 per cent, fibres 51.1 per cent pulses 12.6 per cent milk and milk products 12.3 per cent food articles more than 6 per cent.

मेरा, मान्यवर, इस सिलसिले में सुझाव यह है कि जो यह दिल्ली है, यहां पर तो कुछ व्यवस्था है, लेकिन जो दुरूह इलाके हैं, छोटे-छोटे जिले हैं, सुदूर गांव है, वहां सस्ते गल्ले की दुकानें तो हैं, लेकिन सामान लोगों को उपलब्ध नहीं होता है । लोग राशन-कार्ड लेकर वहां जाते हैं, तो उनको आवश्यक चीजें,

[श्री देव प्रकाश मालवीय]

दैनिक उपयोग की चीजें नहीं मिलती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस राइट की आपने चर्चा की थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है, तो यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन 6 एक्ट के अंतर्गत इस बात का प्रावधान था कि रूल्स बनेंगे और साल भर हो गया इसको पास हुए, लेकिन आज तक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत रूल्स नहीं बने हैं। इस तरह से जो कानून पास किया गया है, उसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है ।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि केवल दिल्ली पर ही निगाह न रखी जाय बल्कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो शहरी इलाकों में छोटे-मोटे कस्बे हैं, मोहल्ले हैं, वहां पर भी आम आदमी को दैनिक उपयोग की चीजें मिल सकें, उपभोक्ता उसका लाभ ले सकें, इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए ।

मान्यवर, एक बात और कहनी है, हमारे देश में फिजूलखर्ची बहुत ज्यादा है। पहले इस देश में जापान महोत्सव हुआ, अब सोवियत महोत्सव हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला चला है इसमें करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हो रहा है । इसके लिये मेरा निवेदन है कि जब इस देश में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है और जैसा कल माननीय गुरुपदस्वामी जी ने कहा कि सवा सौ साल में इतना जबरदस्त सूखा नहीं पड़ा, जितना सूखा इस वर्ष पड़ा है, तो इस प्रकार की फिजूलखर्ची पर रोक लगाएं क्योंकि इस प्रकार की फिजूल खर्ची करके आप केवल गरीब आदमी को तकलीफ देने का, कष्ट देने का काम कर रहे हैं। इसके कारण निरन्तर चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं और किस कद्र कीमतें बढ़ गयी हैं, इस ओर मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। खाने के तेल की कीमत में 40 प्रतिशत से लेकर 45 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है ।

मान्यवर मैं एक उद्धरण पढ़ रहा था, जनवरी, 1985 में जब वर्तमान प्रधानमंत्री सत्ता में आए तो उस समय सरसों का तेल कितना था, आज सरसों का तेल 32 रुपए से लेकर 38 रुपए प्रति किलो है। इसी तरह से रिफाइंड तेल जो 27 रु० में उपलब्ध था आज 42 रुपए से लेकर 50 रुपए के बीच में उपलब्ध है। वनस्पति तेल 20 रुपए 25 पैसे था और इस समय 30 से 35 रुपए में उपलब्ध है। इसी प्रकार से दाल जिसे कि गरीब-से-गरीब आदमी खाता है जो साढ़े 5 रुपए थी उसकी कीमत आज 12 से 15 रुपए किलो हो गयी है। यही हाल चावल, नहाने और कपड़ धोने के साबुन की हालत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि दामों को नियंत्रित किया जाय और गरीब आदमी को सामान उपलब्ध कराने की कोशिश की जाय। आपके सुपर बाजार हैं, सस्ते गल्ले की दुकानें हैं या सहकारी बाजार की दुकानें हैं—उनसे गरीब को सामान मिलना चाहिए, लेकिन

[उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : बैठासीन हुए]

नहीं मिल रहा है बल्कि सरकार अपने कानून से ब्लैक मार्केटियर्स को उपलब्ध करा रही है। मान्यवर, क्या वजह है कि आज सीमेंट दो दामों में मिलता है। अगर परमिट मिल जाय तो सीमेंट की कीमत कम और अगर ओपन मार्केट से लें तो ज्यादा । उसको भी आपने वैधता प्रदान कर दी है । इसी प्रकार चीनी अगर कन्ट्रोल की दुकान में जाइए तो एक कीमत है और ओपन मार्केट में जाइए तो दूसरी कीमत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार की यह जो दोहरी दाम की नीति है इसे समाप्त करना चाहिए। कोई भी चीज हो उसकी एक कीमत होनी चाहिये चाहे कंट्रोल की दुकान में मिले या ओपन मार्केट में। आपकी इस नीति से कंट्रोल की चीजें चोर-बाजारी में चली जाती हैं और इसे बढ़ावा मिलता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि आपको आम आदमी की चीजें सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद ।

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी

हूं कि आपने मुझे मूल्य वृद्धि के सम्बंध में हो रही इस चर्चा में बोलने का मौका दिया। मैं इस सम्बन्ध में अपने कुछ सुझाव देना चाहूंगी।

अभी यहां बहुत से वक्ताओं ने कहा कि हमारे देश की कृषि उपज बढ़ायी जाय। अगर हम हमारे देश की उपज बढ़ाते है तो इससे मूल्य वृद्धि में भी बढ़ावा आएगा क्योंकि अगर चीनी के दाम बढ़ा दिए जाएं तो ये गन्ने के दाम बढ़ाने की बात करते हैं। और अपोजीशन वाले ये बात करते हैं कि एक रुपया चावल हम बेचेंगे और हाउस में ये चर्चा करते हैं कि हमारे देश की कृषि उपज है उसको ज्यादा-से-ज्यादा रेट्स में बेचा जाय। तो मेरा सुझाव यही है कि कृषि उपज के मूल्य में वृद्धि न कर के कृषि उपज के लिए उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे— बीज है, खाद है और सिंचाई के जो साधन हैं, बिजली है— वह सस्ते कर दिए जाने चाहिए। इससे उन लोगों को कृषि उपज में ज्यादा-से-ज्यादा प्रोफिट मिलेगा और इस तरह ज्यादा प्रोडक्शन करके फसल को यदि किसान कम भाव पर भी बेचेंगे तो वह मूल्य वृद्धि नहीं की जाएगी।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अपोजीशन की ओर के एक दो वक्ताओं ने यही कहा है कि मूल्य वृद्धि बढ़ा दी गयी है। तो मैं कहना चाहूंगी कि वे उस जमाने की बात का अंदाजा लगाएं कि उस जमाने में वेतन कितना था। उस समय 10 रुपए एक कांस्टेबल को वेतन दिया जाता था, एक शिक्षक 20 रुपए वेतन पाता था। तो इस लिहाज से चीजों के दाम भी सस्ते थे। लेकिन आज तो हजार, पन्द्रह सौ रुपए तक वेतन दिया जा रहा है। इधर आप वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हैं, उत्पात करते है और पार्टी को बदनाम करते है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। धन्यवाद।

†[کماری سعیدہ خاتون (مدھیہ پردیش) : مانیہ اپ سبھا ادھیکش مہودے- میں آبھاری ہوں کہ آپ نے مجھے قیمتوں میں اضافہ کے سمبند میں ہورہی اس چرچا میں بولنے کا موقع دیا- میں اس سمبند میں اپنے کچھ سجھاؤ دینا چاہتی ہوں-

ابھی یہاں بہت سے وکتاؤں نے کہا کہ ہمارے دیش کی کرشی اپج بڑھائی جائے- اگر ہم ہمارے دیش کی اپج بڑھاتے ہیں تو اس سے قیمتوں کے اضافہ میں چڑھاؤ آئیگا کیونکہ اگر چینی کے دام بڑھا دیئے جائیں تو یہ گنے کے دام بڑھانے کی بات کرتے ہیں- اور اپوزیشن والے یہ بات کرتے ہیں کہ ایک روپیہ چاول ہم بیچیں گے اور ہاؤس میں چرچا کرتے ہیں کہ ہمارے دیش کی کرشی اپج ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ریٹس میں بیچا جائے- تو میرا سجھاؤ یہی ہے کہ کرشی اپج کی قیمت میں اضافہ نہ کرکے کرشی اپج کے لئے اپیوگ میں آنے والی وستوئیں جیسے- بیج ہے- کھاد ہے اور سنچائی کے جو سادھن ہیں- بجلی ہے وہ سستے کردیئے جانے چاہئیے- اس سے ا لوگوں کو کرشی اپج میں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ملے گا- اور اس طرح زیادہ پروڈکشن کرکے فصل کو کو اگر کسان کم بھاو پر بھی بیچیں

t[ ] Transliteration in Arabic script.

[کماری سعیدہ خاتون]

گے تو وہ قیمتوں میں اضافہ نہیں کہا جائیگا -

اپ سبھا ادھیکش مہودے -
اپوزیشن کی طرف سے ایک دو وکتاؤں نے یہی کہا ہے کہ قیمتوں میں اضافہ بڑھادیا گیا ہے - تو میں کہنا چاہونگی کہ وہ اس زمانے کی بات کا اندازہ لگائیں کہ اس زمانے میں ویتن کتنا تھا - اس وقت ۱۰ روپئے ایک کنسٹیبل کو ویتن دیا جاتا تھا - ایک شکشک ۲۰ روپئے ویتن پاتا تھا - تو اس لحاظ سے چیزوں کے دام بھی سستے تھے - لیکن آج تو ہزار پانچ سو روپئے تک ویتن دیا جارہا ہے - ادھر آپ ویتن بڑھانے کیلئے ہڑتال کرتے ہیں - اتپات کرتے ہیں اور پاٹی کو بدنام کرتے ہیں -

انہیں شبدوں کے ساتھ میں اپنی بات سماپت کرتی ہو - دھنیواد -]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Nirmal Chatterjee-

SHRI NIRMAL CHATTERIEE (West Bengal)-. Sir, how many minutes will you give me?

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: Sir, the Finance Minister can reply to-morrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No, today only. He is the last speaker. He will take five minutes.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Sir, Mr. Matto loves me very much. He wants ra: to consume the rest of the time. But I have a meeting at six and I have to go.

Sir, I have heard the discussion with a good deal of interest. A few things seem to have escaped the attention of the House. I want to bring them to the notice of the House and I want the Finance Minister to respond to them.

The most surprising thing is the causes. One of the most serious things that is happening in the country now is that the cost of living index of the agricultural labourers is rising fastest. This is not being noted. As it is, the cost of living index of the industrial workers is rising and touching two digits. I will give you a figure as on October. The growth in the consumer price index of agricultural labourers is fantastic. It is terribly high over the last few months. Now, what does it mean? It means, precisely at this time, because due to the drought the agricultural labourers are having no income, all that is reaching them is rising at a fantastic rate. This is one aspect.

I will now draw your attention to the second aspect. Everybody has said that your administered price policy is creating a problem. Now what the dimension of the problem is, you can imagine. It is not that the administered prices are rising now. They are not. But if the average is 407 with 1970-71 as base, every other heading is less than the wholesale price index of 407 excepting for the goods with administered prices. They have crossed 600. So. the role that the Government is playing in raising the prices is indicated in this.

The point is, during the discusson on drought. I had drawn attention to this that we do not characerize the drought as a nature-made thing. Government's policies have contributed to it. One aspect of this I want to draw your attention to is: Are you aware, or has it ever been told by our Agriculture Ministry, that our agriculture, with the kind of increase in inputs of fertilizers, etc., that you have made, is not yielding as much? Are you aware that despite the increase in productivity, the increase in output is not commensurate with the input that you are putting in? It is one of the most inefficient agricultures in the world. With the same kind

of inputs, many other countries are having a larger degree of productivity. This is a hard fact. Why so?

Sir, I won't consume your time by giving figures. I have got the statistics of almost all these countries. In such countries, those who actually till the soil, those who have genuine interest in the output from agriculture are given this aid and not the renters. It is for this reason, in order to raise agricultural productivity, further, that we are repeatedly insisting that land reforms are a must.

We talk of drought. I sny, this is a mis placed emphasis. Why? In the of the last four years don't you see that agricultural production has not grown? This year it has fallen. But, over the four years since 1983-84, that peak is not being touched in all the subsequent years. That is a danger signal for our economic development. I draw your attention to this. I am being very scrappy and sketchy because I want to leave time for others. Let there be no complacence. I will remind you of another fact. In the course of the last five or six years which was the year of the maximum price rise? You are not aware of that or at least you do not remember it. It is not 1982-83 which was the drought year, but it was the year of our record production, 1983-84. This is another warning signal to us that the maximum rise in prices takes place in the year after the year of drought. Therefore, my question, my apprehension, is: When already in this year it is touching a two-digit figure, what is going to happen next year?

Lastly, I want to make this policy s'atement. I have told this in connection with drought. Sir. this is an opportunity for he Government also, for the ruling party which is in difficulties. They come *to* us and appeal for a consensus. But the whole question is: Can this economic policy that is being pursued in terms of land reforms, in terms of the structure of production, ensure that the prices will not go up? Can there be a consensus on the economic policies without a reversal in your economic policies? We can understand what has happened. You are referring to drought. You want a consensus on drought, on the relief measures. We are with you. But remember that since 1947, despite the growth in production, the price has not come down. Mr. Thakur is not there. He was talking about the law of supply and demand. Supply and demand is taking place since 1947. It is your claim that the production in agriculture and in industry has overtaken the growth in population so that the per capita income has grown. In he course of these 40 years have the prices come down despite the fact of increase in the supply? So this supply and demand theory also over a period has to be understood in a particular sense. He has asked the question; Why then, if there is an excess of supply, the prices rise? It is not the particular question of drought.

To that one answer has been provided, however, in a confused manner by various authorities, that one of the ways is to attack the trade. If you cannot attack the wholesale trade, you cannot have it because supply also means supply as available to the consumers. It is not production which is equal to supply. It is not production which is equally spread over time. There should be control over that supply, and if you do not do that, you cannot have it.

The second most important solution on which there can be no consensus is this. I am concluding, although I have so much to add. Even Mr. Iha who favours most the private sector economy in this country, has agreed in a recent article that unless you change your production structure to the production of more wage goods and less luxury goods, you can never contain the inflationary trend in the economy-Do you, on this, want to have a consensus? You are most welcome to have it. We shall lead that consensus.

Thank you, Sir.

THE MINISTER OF FINANCE AND' THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): Thank you, Sir.

[Shri Narayan Datt Tiwari]

First of all, let me express my hearty gratefulness to the distinguished Members who have participated in this debate.

I am particularly beholden to Shri Balaram, my good old friend, for having raised the debate in very concise, precise and, of course, emphatic terms. I regre-t, I would not be able to agree with him on all he has said. But 1 fully agree with him that we all need a consensus in this regard, and we have look at this question cutting across party lines.

1 am very thankful to my good friend, Shri Gurupadaswamy, for having told the whole country thar we have to act to-act together on a war-footing and that we have no soft options in the long run. Not only in the short-run, but also in the long-run, we may advise ourselves to cut down our expenditure by five to six per cent if the need so arises.

I am also thankful to Nirmal Babu for having drawn our attention towards the agricultural labourers and towards the ad-ministered price policy and to the fact that productivity is not commensurate with the inputs in many parts of the country.

Our? friend, Mr. Matto, was very correct when he said that the rate of inflation in India compared to other developing countries is low. Of course, with them there is *no* comparison but in most of the developing countries of Latin America, from Brazil to Argentina to Mexico, to most ,of the African countries we find the inflation rate is galloping like anything. But here, because of the cooperation of this House and because of the stable economic policy we have been able to contain Ration within limits. Now, there has been a price rise in certain commo-clilies. There is no doubt aboul it. It is just because of the unprecedented drought, because of the fall in agricultural production, because of the fall in production of essential agricultural commodities. Now, take paddy, for example. If there is a shortfall in its production,there is bound to be a little disturbance in the market. I think, with the cooperation of this House we will be able to face this crisis.

I would also like to compliment many State Governments and many officials of the State Governments for doing their best in maintaining the fair price distribution system and also for trying to conlain prices. As I said earlier, it has to be a joint effort. Today all parties, which, are sit ing in this House, are in some State or other sharing power. So; we are all responsible before the people to maintain prices in one way or other. Sitting at Delhi alone and just by issuing orders, we cannoi do the job. The Centre and the States have to cooperate to maintain the price line and to ensure a fair price distribution system. Therefore, I would say that the consensus of the debate has to be a call to the country to unite to fight the after-effects of the drought, to unite to maintain the price line of essential commodities and not to let it go up. Rather we should try to bring them down, to ensure productivity in the coming rabi season and also to see that we take short-term, medium-term and long-term measures to fight the consequences of drought and floods in different par's of the country.

I am Ihankful to my esteemed colleague, Mr. Bhagat, who spoke yesterday. He apprised the House about what we are doing to ensure the supplies of essential commodities through the fair price distri-bution system.

On 28th i.e. day-after-tomorrcw, we are meeting the Chief Secretaries of different States to discuss with, them the *modus operandi* of further strengthening the distribution system and rationalisation of supplies and also find out our deficiencies. There, I would like to urge upon them that the State Governments should set up control rooms in all the districts of the country and there should be a central monitoring room not only to monitor the prices, bin also to monitor supply of essentical commodities. It should not be just a control room to monitor prices. It should also be a control room to maintain supplies. If we have a control room in all the district headquarters, big cities, then at the State level and at our level, we will be able to arrange the infrastractural support for an efficient supplies system. I hope we are

going to suggest to the State Governments to open control rooms in all districts of the country to have regular monitoring of all essential commodities so that there is a smooth flow of essential commodity supplies. I am not complacent. I agree with the Members that there is no question of any complacency. Our hon. friend, Mrs. Renuka Chowdhury warned us that we should prepare for a bad climate next year also. We have to do that and we hope that there will be enough rains. We are still dependent on rains. But let us also prepare as a nation for any eventuality in future. T know that this should not happen. We hope and pray for that. But we have to take all precautions. Therefore T seek the support of all political parties, the broad spectrum of political and economic thinking of this country to mobilise ourselves for this particular responsibility to face any eventuality either today or tomorrow.

Now, hon. Members are aware that we have taken a number of steps to ensure a good rabi crop. We have tried to compensate for khariff income losses through relief employment programmes and special employment programmes to put purchasing power in the hands of the people.

Shri Nirmal Babu had mentioned the plight of the agricultural labourers. You know, Sir, that this distribution system is mainly meant for the present among the poor, agricultural labourers and whatever we are doing under Food for Work Programme, Rural Employment Guarantee Programme or Employment Affirmation Programme is for the agricultural labourers.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: This is very, very inadequate. You can see very little addition that has taken place. I told Shri Bhagatji also that major part is going to the private sector trade. This is an area to which we are repeatedly drawing your attention.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: Now, Rajasthan. Gujarat and many parts of Madhya Praedsh were one of the worst hit areas of drought. This is where our groundnut production, soyabean production atii edible oils production was hit.

It is because of this that we have now imported 1.5 milion tonnes of edible oils to meet the requirements of edible oils and through the public distribution sytem the allocation of additional imported oil has been stepped up progressively from 70,000 tonnes per month in July to nearly 2 lakh tonnes per month during October and November. The latest market reports indicate that as a consequence of these measures the prices of mustard oil and groundnut oil have stopped rising and enabled the State Governments to maintain the supplies, as we send them, to ensure that they do not rise by any means.

I would also like to emphasise that re garding the release of imported edibie oil prices higher than the imported price in fixing the issue price of imported edible oil, we have to keep the farmers interests in mind. Today the domestic cost of edible oil production is higher than the imported prices. It would not be desirable to flood the market with cheap imports and squeeze out domestic production. We do not go back to the PL—480 syndrome. Instead we would like to move to a situation where assured remunerative prices to the farmers would encourage them to produce more oilseeds, achieve self-reliance in the field and save large loss of foreign exchange on this account.

Now, it is very important when we are discussing the price rise that we have also to think of what should be the remunerative prices to the farmers. When we say that the cost of the vegetables is high. at least we can agree that it is mostly the producer who directly sells in the market. There is a wholesale market. But in vegetables the price directly goes to the farmers. In most parts of the country, [he producer comes directly to the market, subji mandis and sells his vegetables. So whenever we are saying that prices of vegetables are going up, we know that the benefit is going to the farmers. Similarly, we have to see when the prices of sugar have gone up. . .*(Interruption).*

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : आलू के बारे में तो यह है कि बिचौलियों के पास ज्यादा मुनाफा जाता है ।

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: The prices of sugar have gone up. Now what do we do? On the one hand, we have *a* demand, I think a reasonable demand thai sugarcane growers should get more. There have been consistent demands that sugarcane growers should get Rs. 31 or Rs. 32 of Rs. *45* per quintal. One or two Stales have anounced the price as Rs. 31 per quintal or Rs 32 per quintal. So when we say that this sugarcane price should be Rs. 32 per quintal, then what would be the sugar price? Naturally, it goes up and then we say that sugar prices have gone up. So. there has to be a balance between the sugarcane price and the sugar price. (*Interruption).*

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: (Andhra Pradesh): The midlemen is getting the benefit and not the growers. The growers and the consumers are suffering.

श्री राम अवधेश सिंह : याज और आलू के बारे में ज्यादा बिचौलियों के पास जाता है ।

SHRI NARAYAN DATT TIWARI. I want that remunerative prices should be paid to the farmers. I myself said it regarding edible oils, if we are to be self-sufficient; we have to pay. It cannot be a sort of unbridled price rise for the farmers. On the one hand, we say the consumers should get things at cheap press, otherwise, what hapens is that we get into a spiral subsidies. If we just analyse how much subsidies we are paying, the exchequer is paying, the economy is payng because of all these distoi lions which we are building up in our economy, then we have to take large amount of subsidies into account that we have to pay because of this gap in the payment that we make to the producers and the price we take from the consumers. Therefore, there has to be some relationship, a reasonable relationship between the prices we pay to the producers and the price we take from the consumers. There has to he this relationship and therefore. T would request that this subsidy aspect— because a large part of deficit is because of subsidies and therefore, the larger the amount of subsidy, the greater danger of our dficit going up. Our subsidies go up and then our deficit goes up- I may clearly mention here that I am not for unreasonable deficit financing I do not stand for a state of affairs where we have deficit financing out of control. But I would also say, that in all economies, taking the rate of growth into account, there is always scope for deficit financing. So therefore, we have to be reasonable about it. There were some figurs given for our deficit financing, our rate of inflation is higher than in many countries... *(Interruptions).*

श्री राम अवधेश सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने परसेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग आप रीजनेबल समझते हैं (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Let him complete his reply. After that, you ask.

श्री राम अवधेश सिंह : आप हमें पूंछने दीजिये, मन्त्री जी बता रहे हैं (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): He is not yielding

SHRI RAM AWADHESH SINGH: He is responding.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE; Mr. Vice-Chairman, Sir, sugarcane will be coming up tomorrow... (*Interruptions).*

श्री राम अवधेश सिंह : आप को मैम्बरों की मदद करनी चाहिये । हम जानकारी करना चाहते हैं । जैसे इन्होंने कहा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग जरूरी है डवलैपिंग इकोनोमी में तो भारत जैसे विकासशील देश में कितने परसेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग जरूरी है ?

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: I did not say this that deficit financing is necessary. I did not say that. मैं सम्मानित मित्र से यह आग्रह करूंगा कि मैंने जो नहीं कहा उसको मेरी जबान में कृपया न रखें । मैंने यह कहा कि घाटे का बजट अनिवार्य नहीं है लेकिन घाटे का बजट

अगर होता है वह ऐसा नहीं है कि जिससे एक सीमा तक हमारी जो आर्थिक वृद्धि है रेट आफ परसेंटेज आफ इकोनोमिक ग्रोथ है अगर उसके साथ तालमेल है और अगर उससे हमारा ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ता है । राष्ट्रीय आमदनी बढ़ती है तो उसका एक प्रतिशत तक हम बर्दाश्त करते हैं ।

6.00 P.M.

श्री राम अवधेश सिंह : कितना परसेंट आप उचित समझते हैं क्योंकि आपका 9 परसेंट है । टोटल बजट का 9 परसेंट डिफिसिट फाइनेंसिंग है । आप कितने परसेंट को उचित समझते हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : जो आकड़े आपको दिये गये हैं वे गलत है ।

श्री राम अवधेश सिंह : यह सदन जानना चाहता है मंत्री महोदय से कि यह कितने परसेंट है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : यह तो डिबेट हो जाती है

There may be different views on this aspect. It becomes a debate.

मैं भी थोड़ी इंकनामिक्स समझता हूं ।

श्री सुखदेव प्रसाद (उत्तर प्रदेश) : **कहां तक आपको जवाब देते रहेंगे ।**

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: The current annual rate of inflation on point-to—point basis, according to the wholesale price index as on 7th November 1987 i« 7.5 per cent as against 6.8 per cent at the same time last year. This higher inflation rate during the current year is on account of supply shortages and inflationary psychology generated by the severe drought cailier in the year. I may mention here that no firm forecast of the inflation rale till the end of the financial year is possible at present until the conditon of the rabi crop is known. As far as the consumer price index is concerned, we have three types of indices on consumer prices. One is for industrial workers; the second for urban non-manual employees; and the third for agricultural labourers.. The movement in the consumer price index is different from that of the wholesale price index because the former reflects only the movement in the prices of the consumer goods and services. The rates used by this index are calculated accordingly. In contrast, the wholesale price index is used to measure the average price movement of all the commodities produced in the economy including intermediate inputs, basic goods and capital goods as well as consumer goods. Therefore, to that extent, I have taken.

SHRl NIRMAL CHATTERJEE I would like to introduce one correction here. The differences also lies in the fact that consumer price includes services which have no wholesale market. Yesteday we were told by the Railway Minister that the prices of items in the Railways have risen in three years, sometimes by 50 per cent, sometimes 100 per cent. This is not reflected in the wholesale price index, but was included in the consumer price index.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI. While I mention that the wholesale price index is used to measure all the comm-ties produced in the economy, unlike the consumer price index, it includes nontangible services like housing, transport, health and education. Now, the greater rise in the consumer price index as compared to the wholesale price index during the current year reflects the fact that as a consequence of the drought, essential tonsuemritems of agricultural origin, in particular pulses and edible oils, have ben in short supply. The prices ofindus-'riai goods that is very important in particular the adminsitered prices of go ids manufactured wholly or partly in the public sector, have been kept stable. I am thankful to Shri Nirmal Babu for reminding me of that. When we consider the economy as a whole, when we consider the whole matrix, this factor of indusrial prices have to be kept in view. Because of the drought, there had ben a fall in certain commodities, in edible oils and pulses. Therefore, we have allowed even the NAFED to import two lakh tonnes of pulses from outside. We have imported edible oils. We are importing pu!ses. We have done so because of the short supply of these commodities.

श्री राम अवधेश सिंह : कोल और पैट्रोल का क्या हाल है जो पब्लिक सेक्टर में है ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जनेश्वर) : बताएंगे । उनको जवाब देने दीजिए ।

SHRI NARAYAN DATT TIWARr Now, we have to pay a little price because of the unprecedented drought. We all agree that thre has been an unprccednted drought. This is the price that we pay. must congratulate everybody on having put our efforts together to fight (he situation. I am sure we can over come the situation if we all keep together and fight the consequences of the drought and see to it that the public distribution system is well-mainained and that we all create a climate—sometimes by our speeches alone we create an atmosphere where prices rise. If somebody wants to keep down the I rices, we should also try to create a proper atmosphere where there is no panic.

कीमतें बढ़ रही हैं, गजब हो रहा है, महंगाई आसमान छू रही है

—this sort of statements further aggravate the situation. If you do cooperate in his endeavour. I should also contribute by raising my little voice. Of course, we should present the situation as it exists. But let us not exaggerate the situation which also 'cads to higher prices.

Then I come to money supply about which Mr. Kulkarni spoke. The Reserve Bank of India has been very cautious on this. The money supply in the current financial year is 7.7 per cent lower than 'he relevant period in 1986-87 when it saw a rise of 8.8 per cent. The money supply now is lower—7.7 per cent. The ne. bank creditto Government has risen in a lower percentage of 12.1 compared !o 14.3 in the coresponding period last year. The total bank credit has also risen at a lower percentage rate of computed to the growth of 4.1 per cent in the year 1986-87. The food credit has declined in the current financial year so for by 31.2 per cent. It also reflects a lesser procurement Non-food credit hsa lisen by 6.9 per cent compare to a lower growth of 4.5 per cent in the corresponding period in 1986-87. The overall stress of the monetary authorites is to contain the excessive growth in money supply and prevent the use of bank credit for specu tative purposes, without denying genune demands for credit in productive and trade sector. Accordingly, the cash receipts —CRR—has been raised from 9.5 per cent to 10 per cent of net demand and time liability of commercial banks is mopped up by ex;esive liquidity arising from the flow-back of food credit. During July to August, 1987 in Ihe ease of oilseeds, vegetable oils, the minimum margins were raised across the board by 15 per cent points. Again raw cotton and coiton-seeds which had earlier been exempt were brought back under the purview of selective credit control. Subsequently on October 19 1987 the minimum margins of paddy rice and pulses were raised by 15 per cent points All this was done so that there should be no boarding there should be no potential for boarding of these essential commodities. The Reserve Bank has taken immediate steps to ensure that these would not go up. that deficit financing should not go *up.* that monetary control is maintained and that also there is no potential market to hoard goods and essential commodities.

Now, regaring deficit financing many Members have comented that we should not allow dficit fienancing to incrase. Wt have already taken steps.While in drought relie we shall have an adidtional expenditure of Rs 1350 crores to meet the drought expenditure—this is in addition to what has been provided in the Budget to meet this additional need for resources, the Central Government has already in-nialed economic measures which are expected to yeild a saving of Rs 650 crores. Resides, measures have been taken to ir,ise about Rs. 550 crores through additional taxation. Tt is found that small savings collection may be adversely affected by the drought and it may fall short of the Budgeted estimates by Rs. 300 crores. On th? other hand, mobilisation and acce-lerated distribution of external assistance is likely to add to our receipts. T also hope that there will be an increase in the other heads of revenue. I have tried my level best: T have had meetings with the direct and indirect tax officials; I have had three

or four meetings with them and I am trying very much, very hard, to see that they would be able to mop up resources within ihe tax structure. But, in future, we might have to cut further expenditure and. therefore, we are having that exercise also with the respective Ministers, with all the Ministers and with the Planning Commission to see as to how far we can cut the non-Plan expenditure. We do *not* want *to cut* down the Plan; I may say that here. Tt is because of the fact that if we cut down the Plan expenditure, then would be very difficult for us in the future years. Therefore, without cutting the Plan, if we can reduce the expenditure on non-Plan items, that would be better and that exercise we are doing.We have also asked the Bureau of Public Enterprises to have intensive discussions with the public sector undertakings so that they can also take steps to reduce the non-Plan expenditure in the public sector undertakings and they can also have eco-nombs. But I would also like to request the S ate Governments in this connection and here I agree perfectly with Mr. Balaram, with what he said yesterday. He said that the State Governments also have to see that they bring about economics in their non-Plan expenditure. We have already discussed with the Chief Ministers when the Prime Minister took the meeting with them regarding drought and we will again be addressing the Chief Secretaries the day after tomorrow to see that all possible steps are taken to economise on non-Plan expenditure in the States.

1 would also request the employees in the public sector undertakings, in the Central Government and also in the State Governments to deposit in the Provident Fund Account whatever portion of DA) they can deposit voluntarily. They can do i! voluntarily because, as was very ad by one of our friends here, DA. also adds to this constant of DA also adds to this. I think it was Mr. Kadharshn who said this. Yes, T remember, Mr. Kadharsha mentioned the day before yes-terdiy that the impact of the DA is there on the exchequer. It has an impact not only on the exchequer, but also on the inflationary situation as such. It has alsoi inflationary potential if we do nop take care of it and, therefore, I appeal to the State Government employees to deposit... SHRI NIRMAL CHATTERJEE; He has put the cart before the horse. The prices rise first and then the DA is given.

SHRI NARAYAN DATT TIWAR1: What Mr. Kadharsha said is that this is a cycle, this is an inflationary cycle.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Just one minute. The employees also were asking me to put it across to you this: Is your appeal to deposit a portion of the DA in the PF Account accompanied by tax concessions also? This is what they are asking.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: *What* concession?

SHRI NIRMAL CHATTERJEE; You see, when they deposit money in the PF Account, after the initial six thousand on the first six thousand rupees they get a concession or exemption up to fifty per cent, on the next they get forty per cent exemption and so on. They say that in respect of this compulsory deposit also they should get concession in Income-Tax.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: We are not asking for any compulstory deposit.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: You are not compelling them. But they say, *"We* are prepared to do it. Make it tax-free completely.". This is what they say.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: What I am asking for is voluntarily depositing in the Provident Fund Account, not only here at the Centre, but also in the public sector undertakings and also in the State Governments. What I mean to say is that this has to be across the Board.

Sir, it is not possible nor it is wise to say that there will be no further inflation in the year of severe drought. I *can tell* the House that we have to take all possible steps to contain the inflation and I can assure the House that we will take all possible steps to see that it does not reach the double-digit level. We are happy that at least we have not allowed it to reach the level of 1979-80 when we

[Shri Narayan Datt Tiwari]

had a drought situation more or less of the same dimension. But there is every likelyhood that we will not reach inflation rate and I would like to have the cooperation of all the State Governments in this.

Now, Sir, some honourable Members had expressed their concern about the declining purchasing power of the rupee. While inflation inevitably erodes the purchasing power of the rupee, it does not necessarily erode the purchasing power of the average consumer so long as the rise in per capita money income more than offsets the rise in prices. Now, between 1970-71 to 1985-86, the Consumer Price Index increased by 3.34 times. However, the per capita income at current prices rose by 4.1 times. This implies that per capita real purchasing power has actually increased by about 23 per cent over this period despite the fall in purchasing power of the rupee. I have before me... *(Interruptions)*

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: But in this period the Birlas have increased their assets a hundred times; the poor remain poor... *(Interruptions)*

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: I do not want to bale out arguments to my learned Professor of Economics from Andhra Pradesh. Of course, Malaviyaji. *(Interruptions)*

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : 11 करोड़ में से 5 करोड़ 30 लाख आदमी तो केवल उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मालवीय जी तो हमारे पुराने मित्र हैं । उनसे मैं क्या कहूं । लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि आज गरीब-से-गरीब किसि मजदूर की स्थिति भी आज से दस साल पहले से अच्छी है ।

श्री राम अवधेश सिंह : आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : पहले चार आने मिलते थे . . . (व्यवधान) . . .

श्री राम अवधेश सिंह : चार आने में एक सेर चावल मिलता था आज चार रुपए में मिलता है ।

Now, Shri N. E. Balaram mentioned that prices have been rising due to Government policies relaing to administered prices. According to the hon. Member, the Government has increased the prices of cement, sugar, drugs and textiles. As a matter of fact, the prices of administered items have remained relatively stable during the last two years. The index for administered items including petroleum products, electricity, fertilizers, iron and steel, sugar and cement have gone up only 1 per cent so far during the current year. The prices of these items remained stable in the previous year also. It is, therefore, not quite correct to- say that the increases in the prices of administered items are responsible for the inflationary trends.

श्री राम अवधेश सिंह : पैट्रोल का भी बताइए ?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आप हरेक बात के बाद कमेंट करेंगे तो जवाब कैसे पूरा होगा ।

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: Shri M. S. Bhandare made a mention about the rise in prices of sugar and stated that the monthly releases should have been increased to maintain the prices of sugar under check. As a matter of fact, the prices of sugar have remained relatively stable. They have gone up by less than 3 per cent during the current year because of the higher releases about which I have mentioned earlier.

Shri M. A. Baby raised the issvie of nationalisation of wholesale foodgrain trade. I would like to remind the House that the Government had already experimented with the take-over of wholesale foodgrains trade some 15 years ago. The experiment dislocated trade, caused difficulties for the farmer and undue hardship for the consuming public. Government does not, therefore, consider it either desirable or feasible to repeat the experiment.

Shrimati Renuka Chowdhary has expressed concern about the adequacy of stocks of rice. It may be mentioned that at the beginning of October 1987 we had adequate stock of 5.5 million tonnes of rice. This level of stock on the eve of the new marketing season for rice should be adequate. The normal requirement of stock level at this time is about 2 million tonnes. The procurement of rice in recent years has been of the order of 9-10 million tonnes which is mors than the normal requirement of about *8i* million tonnes. During the current year, while the procurement is likely to be lower, the off-take is likely to go up. As the procurement season has just begun, it is not possible to make a firm estimate of the likely procurement during the coming months. But I am happy to inform the House that reports from Punjab are very significant. They are doing very well as far as procurement is concerned. They will be procuring only a little less than last year, as far as the latest reports go. But in Haryana—it is surprising and I' would like to verify it—the report say that 1100000 tonnes came to the *mandis* and only 100000 tonnes were procured. I will have to enquire into it. We have to strengthen our procurement machinery. Again, it is up to the States to do it. *(Interruptions)* It is again up to the States. 1 would like to suggest that the State Government do take notice of what has been discussed here today in this House and they should gear up their procurement machinery. Unless they procure, how can we distribute?

PROF. C. LAKSHMANNA (Andhra Pradesh): Is there any relation between this thing and what was said by Mr. Bhagat yesterday that we will be importing rice?

SHRI NARAYAN DATT T1WARI: I am coming to that. At the point of procurement, we have to procure as much as we can. Therefore. I would emphatically suggest that the State Governments do gear up their procurement machinery. I think it is a very timely debut.; and the State Governments must take notice of this debate. They must gear up their procurement machinery. The Government is keeping a vigilant eye on the level of stocks. At any point of time *if* it is told that the procurement is likely to fall shoal of the quantity required to maintain adequate supplies for the public distribution system, arrangements will be made to supplement domestic availability of rice through imports. This announcement alone should be enough to keep down the prices. They should know that if they want to raise prices, we are ready toi import. This announcement itself is a damper on those who want to inflate prices. *I* have said it earlier also. I would like to caution them again.

Shri Pramod Mahajan mentioned that the Government has not taken action against black-marketeers. Mr. Bhagat has given you certain figures. I would like to repeat that the enforcement agencies have intensified the detection of violation of the Essential Commodities Act and the prescribed stock limits. During the 3-1/2 months from the beginnig of August, 1987, 31,865 raids were carried out and prosecutions were launched against 1297 offenders. The value of goods seized during these 3-1 [2 months was Rs. 11.20 crores as against just over Rs. 10 crore.s during the entire year of 1986. I would request the hon. Members to plead with their respective State Governments to be more effective in this matter. As you go back to your capital cities and State headquarters, I hope you will be meeting the Chief Ministers and the Civil Supplies Ministers. They should get their enforcement machinery tightened. I am satisfied with whatever has been done. 3ut I would like more to be done. I am one with the hon. Members that we should be more vigilant and we should take more stringent action against hoarders and black-marketeers. I am one with them on this regard and I hope that the State Governments will heed the sentiments of the House.

Many hon. Members emphasised the need for strengthening the public distribution system. These suggestions have been noted by my colleague, the Civil Supplies Minister. T will also take note of the suggestions. We have also contracted representatives of the specified voluntary organisations who have been given statu-

[Shri Narayan Dalt Tiwari]

tory powers to visit retail outlets, hear the grievances of the consumers and forward the complaints and suggestions to the Civil Supplies Department. Many State Governments have set up Departments of Consumer Affairs with the objective of promoting and strengthening the consumer protection movements.

Many hon. Members referred to smuggling and the crisis in gold. Traditionally, there has been a tendency towards smuggling of gold into the country clue to high domestic demand on account of social customs and hoarding of gold as a secured asset, negligible indigenous production and domestic supply as compared to demand and high profitability due to wide differencial between lower international prices and high domestic price. Now, the gold prices have gone up also because of intensification of anti-smuggling measures. Recently, I have myself held five meetings with the Customs Officers and co-ordinated anti-smuggling activities. It has become more effective and now it has also reflected in the price of gold going up. So, now there has been a suggestion that we should have some channel by which legal gold supply can be maintained in the country. Yesterday, I had an occasion of meeting the representatives of the All-India Sharaaf Association. I told them, and I would like to inform this House also, that the Rangarajan Committee is now looking into all the aspects of gold control rules and supply of gold. And I would like the committee to consider all the suggestions made in this House also as to what we should do. On the one hand we have to see that the black money is not converted into gold. On the other, because of the religious customs and marriages, we should have some gold supply available. We should not choke off all supplies of gold. That should not be done. Therefore, about what should be done, the Rangarajan Committee will go through all the suggestions made here and then give their considered suggestions.

Sir, apart from gold prices, we have launched antismuggling drives in all fields—I against textiles and against electronics. And I am very happy to inform the House that all these measures have been successful to a large extent and I am sure that our officials will do all the more in this regard so that this transformation of black money into smuggled goods, whether electronics or gold or textiles is reduced. But we have to do more in this regard. And we would like the consumer movement not only to educate the consumers regarding the distribution of food-grains but also to ensure that they have a spirit of *swadeshi.* Why should we use smuggled goods? Why should there be so much scope for foreign goods in our country? The spirit of *swadeshi* should come. I assure that our consumer's movement would inculcate the spirit of *swadeshi* which had been the endeavour of our national leaders in this regard. Sir, I am reminded of what Rigveda and Manusmriti said. Manusmriti in Chapter 6—128 said:

यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम ।
तथावेक्ष्य [illegible] राष्ट्रे कल्पमत्स्तरं [illegible] ।।

It prescribed that tax and prices should be according to the abilities of the persons to pay.

उपोहश्च समुहश्च क्षत्तरो ते प्रतापते ।
ता त्रिह बहुधा कांति बहु भूमानमा हितं ।।

This is from Atharvaveda which emphasises the strategic importance of capital accumulation and just distribution of the produce in promoting rapid growth and prosperity.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: But you are not following it.

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: HeThat is what we are following. This is what our Athavaveda and Manusmriti said. Even in those ancient days, they have give us the guidelines which we follow correctly. We hope we can deal with all the problems of our national economy which we face today. Thank you, Sir. *(Interruptions')*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I will allow only Mr. Balaram because he has moved it. *(Interruptions)*

SHRI N. E. BALARAM (Kerala): Sir, I consider that the hon. Finance Minister has not given a final reply because he gave an assurance that he will be watching the price situation and he will take necessary measures. In the light of that, I would like to draw your attention to one or two points. Sir, I am not making a speech. Sir, our agricultural production for the last four years has been stagnating around 150 million tonnes. He should take note of it. Unless we take strong measures to expand and improve the productivity of agriculture even in the eastern region, the production is not going to improve. That is my first point. Secondly, for the last one year, the growth of manufacturing sector is declining. I underline this that the growth of manufacturing is declining. I have no time, otherwise I would have quoted some statistics. The Minister should think about it. Thirdly, there is a terrible distortion i* the prices given to the agriculturists and the prices of commodities in the market. That price distortion should be corrected. I will give you one example. Take, for instance, the case of sugar industry. The rate of profit in the sugar industry has gone up by 17 per cent. But the price of cane has gone up by only 3 per cent. It is a distortion that while the price of sugar has gone up by 20 per cent the price of cane should go up by only 3 per cent. This is a terrible distortion. Something must be done in this regard. I can cite so many examples like this.

I do not agree that the administered price policy has had a salutary effect. When the supplementary grant? are taken up for a discussion in the House, I will speak on it at that time. I can definitely tell you that one-third of the rise in prices is due to the component of administered prices. T will explain to you this factor when there is time. At the moment, I am only bringing these points to your notice. You have to take all these matters seriously into account.

SHRI NARAYAN DATT TIWA] Sir, first of all, regarding stagnation agricultural production, I may say that Seventh Five-Year Plan is geared exa to meet this situation. We are plan to set up ten fertilizer factories, gas-ba plants at Hajira, Babrala and other pla Then there is the special paddy produd programme for the eastern region of country. The Seventh Five Year Plan highlighted exactly these requirements a breakthrough in agricultural product and removal of stagnation in product in the eastern region. As far as growth ...

THE VICE-CHAIRMAN (SI JAGESH DESAI): He has given all information only for your noting.

SHRI GHULAM RASOOL MAT! Sir, .many points have been.raised in House. Will the hon. Minister assure that the officers who have taken note what we have said here will take notice of it and take, the required fol up ac'ion?

SHRI NARAYAN DATT TIWA] All right.

श्री राम अवधेश सिंह : माननीय वि मंत्री जी समाजवादी रहे...

श्री नारायण दत्त तिवारी : हूं ।

श्री राम अवधेश सिंह : मैंने कहा रा मैं जानना चाहता हूं तीन बातें ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) केवल एक मिनट में ।

श्री राम अवधेश सिंह : पहली बात कि डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में इन्ह कहा तो मैं बताना चाहता हूं कि 1980 1800 करोड़ का था.....

उपसभाध्यक्ष : यह सब जानते हैं आपने जो पूछना है वह पूछिए ।

श्री राम अवधेश सिंह : अभी पिछ साल 3600 करोड़ था और इस साल 58(

[श्री रामअवधेश सिंह]

करोड़ है। टोटल बजट 62 हजार करोड़ का है। 62 हजार करोड़ में से 5800 करोड़, लगभग 9 परसेंट हुआ। 9 परसेंट डेफिसिट फाइनेंसिंग होगा। तो प्राइसेज निश्चित तौर पर तीन गुना बढ़ेंगे। दूसरी बात इन्होंने कहीं परचेजिंग पावर के बारे में। परचेजिंग पावर अगर बढ़ी तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। यह बात मैं नहीं जानता कि किस अर्थशास्त्र के नियम में ऐसा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा और मनी की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। यह दोनों में विरोधाभास है। जहां इन्फ्लेशन बढ़ेगा वहां परचेजिंग पावर मनी की घटती चली जाती है यह अर्थशास्त्र का सर्वमान्य सिद्धांत है। परचेजिंग पावर घटेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी बतायेंगे कि अगले वर्ष डेफिसिट फाइनेंसिंग बढ़ेगा नहीं बल्कि 5800 करोड़ से नीचे जाएगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी : यह बजट बतायेगा।

श्री राम अवधेश सिंह : 10 हजार करोड़ से कम नहीं होगा, यह मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं। आप डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं बढ़ने देंगे यह बता दीजिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जब कभी हम तुलना करते हैं डेफिसिटी फाइनेंसिंग के बारे में तो वह आपके ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के आधार पर, राष्ट्रीय जो आमदनी होती है उससे तुलना की जाती है। बजट से कहीं तुलना नहीं होती संसार भर में। आम तौर पर जो तुलना होती है, तुलना वैसे भी कर सकते हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, लेकिन तुलना जो सारे संसार के अर्थशास्त्री करते हैं वह ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स से करते हैं कि इसका प्रतिशत कितना है, उससे तुलना होती है। वैसे जैसे चाहें आप कर सकते हैं, मैं यह नहीं कहता कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन तुलना ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स से होती है।

दूसरा मुद्रा-स्फीति का सवाल है कि यह कितनी है। मुद्रा स्फीति का संबंध देश की आर्थिक वृद्धि की विकास दर से होता है। विकास की दृष्टि से हम थोड़ा बहुत डेफिसिट फाइनेंसिंग बर्दाश्त कर सकते हैं और मुद्रा स्फीति का मुकाबला कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। जहां तक सवाल है कि आगे क्या होगा हम आशा करते हैं कि आगे अच्छा होगा।...(व्यवधान)... एक समाजवादी का आशीर्वाद दूसरे समाजवादी को मिल जाय तो बहुत है।

ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT LEGISLATIVE BUSINESS

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 26th November, 1987, allotted time for Government Legislative Business as follows:

Business	*Time Allotted*
Consideration and passing of the following Bills, as passed by the Lok Sabha:—	
(a) The Railway Claims Tribunal Bill, 1987.	2 hrs.
(b) The National Housing Bank Bill, 1987.	4 hrs.
(c) The Regional Rural Banks (Amendment) Bill, 1987.	

THE VICE-CHAIRMAN (SHR1 JAGESH DESAI): The Home stands adjourned till eleven of the clock tomorrow, the 27th November, 1987.

The House then adjourned at thirtyseven minutes past six of the clock, till eleven of the clock on Friday, the 27th November, 1987.